सिविल सर्विसेज मिनर्वा

सामान्य अध्ययन

वर्ष 12, अंक 11, नवंबर, 2017

मूल्य : 50 रुपये

अनुक्रमणिका

राष्ट्रीय समसामयिकी **4**
सौभाग्य योजना 4
ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 103वीं रैंक 4
ओडिशा ने व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया 4
कोंकणी साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को 'सरस्वती सम्मान' 4
सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र 5
सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना 5
चकमा और हजोंग शरणार्थियों को भारत की नागरिकता 5
फैसले के बाद सरकार के सामने चुनौतियाँ 6
क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है ? 6
राष्ट्रीय पेंशन योजना में खाता खुलवाने की आयु सीमा बढ़कर 65 साल हो गई 6
देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी 6
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2017 घोषित 6
राजीव गांधी खेल रत्न 2017 6
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017 6
चेनानी–नाशरी सुरंग 6
वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017 7
मेधा 7
भारत और विश्व **8**
ब्रिटेन की संसद ने पारित किया ब्रेग्जिट विधेयक 8
मधेसी 8
नेपाल के नए संविधान में मधेसी दोयम दर्जे के नागरिक 8
अर्थव्यवस्था / वाणिज्य **9**
प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण आवास योजना– 'ग्रामीण' का क्रियान्वयन 9
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' 9
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 143वां स्थान 9
विज्ञान और प्रौद्योगिकी **10**
इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर बनाया विश्व रिकॉर्ड 10
भारत का अंतरिक्ष का सफर 10
54 साल पहले लॉन्चिंग 10
42 साल पहले पहला सैटेलाइट 10
38 साल पहले पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 10
24 साल पहले लॉन्च हुआ चैस्ट 10
ये तीन कामयाबी जिन्होंने दुनिया को चौंकाया 10
चंद्रयान–1 10
मंगलयान–1 10
104 सैटेलाइट्स एकसाथ लॉन्च किए 10
आगे क्या है इसरो की प्लानिंग? 11
क्या है रैंजमवेयर साइबर अटैक ? 11
रक्षा / प्रतिरक्षा **12**
जीबीयू–43 12
इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण 12
पुरस्कार / सम्मान **13**
नोबेल पुरस्कार 2017 13
नोबेल शांति पुरस्कार 2017 13
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 13
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2017 13
पुलित्जर पुरस्कार 2017 13
रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2017 14
भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2017 14
अर्थशास्त्र का नोबेल 2017 14
89वां ऑस्कर अवॉर्ड 14
59वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड 2017 15
विजेताओं के नाम 15

Editorial and Corporate Office
Rajrooppur, Allahabad
RNI
UPHINDI/2005/26617
Publisher, Editor and Owner
Dheer Singh Rajput
Allahabad; Year 12, Issue 11, November, 2017
Place of Publication & Registerd Office
331/240 A, Stainly Road, Nayapura, Allahabad (UP)
Printing Press & Address
Academy Press Daraganj, Allahabad (UP)
Website : www.developindianewspaper.com
E-mails : civilservicesminerva@gmail.com

संपादकीय और कॉरपोरेट ऑफिस
राजरूपपुर, इलाहाबाद
आरएनआई
UPHINDI/2005/26617
प्रकाशक, संपादक, और स्वामी
धीर सिंह राजपूत
इलाहाबाद, वर्ष 12, अंक 11, नवंबर, 2017
प्रकाशन का स्थान और रजिस्टर्ड ऑफिस
331/240 ए, स्टैनली रोड, नयापुरा, इलाहाबाद (उ.प्र.)
प्रिंटिंग प्रेस का पता
एकेडमी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद (उ.प्र.)
वेबसाइट : www.developindianewspaper.com
ई–मेल : civilservicesminerva@gmail.com

http://www.developindiagroup.co.in/

Read

Only in 500/- per year

Develop India

https://www.developindiagroup.co.in/

Develop India

Only in 500/- per year

Online Subscription

https://www.developindiagroup.co.in/

राष्ट्रीय समसामयिकी

सौभाग्य योजना

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब सिर्फ 3000 से भी कम गांव ऐसे बचे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है. लेकिन, सरकार भी मानती है कि देश में चार करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है और वह अंधेरे में जीने को मजबूर हैं. 25.09.2017 को यह ऐलान किया कि अब वह इस स्थिति को बदलने जा रही है. *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती के मौके पर सौभाग्य नाम की योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद है हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना.*

इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह खुद मिट्टी तेल के दीए में पढ़ चुके हैं और इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची है वहां जिंदगी कितनी मुश्किल होती है. उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना से 2018 दिसंबर तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश में कोई भी घर अंधेरे में ना रहे. यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इसे एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहेगी.

सौभाग्य योजना के लिए सरकार ने 16,320 करोड़ रुपये का बजट रखा है और हर घर तक बिजली पहुंचाने का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी 10: खर्च राज्य सरकारों को उठाना होगा और 30: बैंकों से लोन लिया जाएगा. इस योजना की खास बात यह है कि लोगों को अपने घर में बिजली कनेक्शन पाने के लिए कोई खर्च नहीं करना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद बिजली का कनेक्शन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने का सिलसिला भी बंद हो जाएगा. क्योंकि सरकार खुद लोगों के घर–घर जाकर बिजली कनेक्शन लगाएगी और उन लोगों की पहचान करेगी जिनके घर बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं है.

प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप का सहारा लिया जाएगा और लोग बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन देने से लेकर सारी कार्यवाही मोबाइल के जरिए ही पूरी कर सकेंगे. गरीब लोगों के लिए बिजली कनेक्शन पाने की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त होगी. लेकिन बाकी लोगों को भी इसके लिए सिर्फ 500 खर्च करने होंगे और वह भी 10 किश्तों में बिजली बिल के साथ लिया जाएगा.

देश के दूरदराज इलाकों में जहां हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाना मुश्किल है वहां सरकार घरों को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा का सहारा लेगी और लोगों को बैटरी, 5 LED लाइट और एक पंखा भी दिया जाएगा.

सौभाग्य योजना से पहले *मोदी सरकार ने हर घर तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई थी जिसके तहत अब तक तीन करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन बांटे जा चुके हैं.* उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनाव में BJP को उज्वला योजना का जबरदस्त फायदा मिला.

ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 103वीं रैंक

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक) में 130 देशों की लिस्ट में भारत 103वें स्थान पर है। ये रैंक ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका) में भी सबसे नीचे है। नॉर्वे इस लिस्ट में टॉप पर है। ये इंडेक्स इस बात का संकेत होता है कि कौन–सा देश अपने लोगों के डेवलपमेंट, उनकी टीचिंग–ट्रेनिंग और टैलेंट के इस्तेमाल में कितना आगे है।

इस बार की लिस्ट में नॉर्वे ने टॉप पर जगह बनाई है और इस देश ने पिछले बार के टॉप पर बरकरार फिनलैंड को इस बार दूसरे स्थान पर धकेल दिया है।

जेनेवा के डब्ल्यूईएफ (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इम्प्लॉयमेंट में जेंडर गैप के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे पीछे है। हालांकि फ्यूचर के लिए जरूरी स्किल्स के डेवलपमेंट के मामले में भारत की स्थिति बेहतर है और इस मामले में 130 देशों के बीच इसकी रैंक 65 है। फोरम ने पिछले साल की अपनी रिपोर्ट में भारत को 105वीं रैंक दी थी और कहा था कि यह देश अपनी ह्यूमन कैपिटल की संभावनाओं का सिर्फ 57 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पा रहा है। उस लिस्ट में फिनलैंड टॉप पर था। WEF की लिस्ट किसी देश के लोगों की नॉलेज और स्किल के आधार पर तैयार होती है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में उस देश की वैल्यू को बताती है और उसकी ह्यूमन कैपिटल रैंक तय करती है।

WEF के मुताबिक इस साल की लिस्ट में ब्रिक्स देशों में रूस सबसे आगे है। उसे 16वीं रैंक मिली है। चीन को 34वीं, ब्राजील को 77वीं और साउथ अफ्रीका को 87वीं रैंक हासिल हुई है। नई लिस्ट में शामिल साउथ एशिया के देशों में भारत, श्रीलंका और नेपाल से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आगे है। **ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत के पीछे रह जाने की रिपोर्ट में कई वजहें बताई गई** हैं। मसलन– *एजुकेशन की फील्ड में पिछड़ना* और *ह्यूमन कैपिटल का कम फैलाव होना*। WEF के मुताबिक इसका मतलब है कि *भारत में अवलेबल स्किल का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है*।

ओडिशा ने व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया

देश के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त डॉ. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि (27.07.2017) पर उन्हें देशभर में याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि पर ओडिशा सरकार ने भद्रक जिले में बाहरी ***व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा*** है.

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री महेश्वर मोहंती ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद कल गजट अधिसूचना जारी की. मोहंती ने गजट अधिसूचना की एक प्रति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सौंपी , जिन्होंने पूर्व में व्हीलर द्वीप का नाम कलाम के नाम पर करने की घोषणा की है.

पटनायक ने पूर्व राष्ट्रपति की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दीं. समारोह में उन्होंने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप और बालेश्वर जिले में चांदीपुर के अस्थायी प्रक्षेपण स्थल से कलाम के भावनात्मक जुड़ाव को याद किया. श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाम ने देश की प्रतिरक्षा के लिए मिसाइल विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत इन दो जगहों पर सबसे अधिक समय बिताया हैं.

कोंकणी साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को 'सरस्वती सम्मान'

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान अगले हफ्ते कोंकणी साहित्यकार महाबलेश्वर सैल को दिया जाएगा.

के के बिरला फाउंडेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि वर्ष 2016 का 'सरस्वती सम्मान' आगामी 30 अगस्त को यहां राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा सैल को उनके उपन्यास 'होथन' के लिए दिया जाएगा.

74 वर्षीय लेखक ने चार मराठी नाटक और सात कोंकणी उपन्यास लिखे हैं. इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा में पांच लघु कथाएं और एक उपन्यास भी लिखा है. फाउंडेशन के लिए इस पुरस्कार में 15 लाख रुपये का नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है. पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था.

सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अब पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने के फरमान को दंडनीय अपराध बनाया गया है और ऐसे मामलों में दोषी को सात साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह का कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार रोकथाम अधिनियम, 2015 को पिछले महीने मंजूरी दी और इसे तीन जुलाई को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

कानून के तहत सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी करने वाले जाति और समुदाय परिषद जैसे अर्द्धन्यायिक इकाइयों के सदस्यों को सात साल तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य विधानसभा ने 13 अप्रैल, 2016 को विधेयक को पारित किया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था।

सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में नागरिक के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। इसके साथ ही निजता अब मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज केएस पुट्टस्वामी ने सन् 2012 में श्आधारश् को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले समेत 21 पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने फैसला देते हुए कहा है कि प्राइवेसी या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है.

संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकार के प्रावधान हैं, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था. अनुच्छेद–21 में जीवन तथा स्वतन्त्रता का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में निर्णय देकर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल्द न्याय, अच्छे पर्यावरण आदि को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है. संविधान के अनुच्छेद–141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून माना जाता है, और अब प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गई है. मौलिक अधिकार होने के बाद कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करके न्याय की मांग कर सकता है.

सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया कि प्राइवेसी कॉमन लॉ के तहत कानून तो है पर इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता. इस बारे में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पुराने दो फैसलों खड़क सिंह (1954) और एमपी शर्मा (1962) की जोरदार दलील दी गई थी. पिटीशनर्स के अनुसार संविधान में जनता सर्वोपरि है तो फिर प्राइवेसी को मौलिक अधिकार क्यों नहीं माना जाना चाहिए? पिटीशंस ने अमेरिका में प्राइवेसी के बारे में चौथे अमेंडमेंट समेत कई अन्य दलीलें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशनर्स की तरफ से पेश दलीलों को मानते हुए प्राइवेसी को मौलिक अधिकार मान लिया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले लगाई रोक के बावजूद सरकार द्वारा श्आधारश् को 92 कल्याणकारी योजनाओं में अनिवार्य बना दिया गया था. आधार के तहत लोगों को निजी सूचनाओं के साथ बायोमैट्रिक्स यानि फेस डिटेल्स, अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के निशान देने पड़ते हैं. श्आधारश् को इनकम टैक्स समेत कई अन्य जगहों पर जरूरी कर दिया गया है. श्आधारश् की अनिवार्यता और बायोमैट्रिक्स के सरकारी डेटाबेस को प्राइवेसी के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी. इस मामले में पहले तीन जजों की बेंच में और फिर पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की. खड़कसिंह मामले में 8 जजों की बेंच ने फैसला दिया था इसलिए प्राइवेसी के मामले पर फैसले के लिए नौ जजों की बेंच बनाई गई. संविधान पीठ के इस फैसले के बाद अब पांच जजों की बेंच श्आधारश् मामले पर सुनवाई करेगी.

आधार के अलावा सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पालिसी को चुनौती दी गई थी. प्राइवेसी पर संविधान पीठ के फैसले के बाद व्हाट्सऐप मामले पर पांच जजों की बेंच सुनवाई

चकमा और हजोंग शरणार्थियों को भारत की नागरिकता

देश में 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बहस तेज है। इस बीच देश में चकमा और हजोंग शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी गई है। ***चकमा और हजोंग शरणार्थी भारत में बांग्लादेश के चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों से आए*** हैं। *इन लोगों की जमीनें 1960 के दशक में वहां कर्णाफुली नदी पर बनी कापताई बांध परियोजना में चली गई* थीं। इसके अलावा धार्मिक उत्पीड़न का भी इन्हें शिकार होना पड़ा है। चकमा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि हजोंग हिंदू हैं।

चकमा लोग बंगाली–असमिया भाषा से मिलती–जुलती भाषा बोलते हैं। *हजोंग तिब्बती–बर्मी भाषा बोलते* हैं, हालांकि इसे असमिया की तरह ही लिखा जाता है।

फिलहाल भारत में लगभग 1 लाख चकमा और हजोंग शरणार्थी रह रहे हैं। वर्ष 1964 में जब ये लोग भारत आए थे, तब करीब 15,000 चकमा थे और 2,000 हजोंग थे। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक शुरुआती दौर में भारत आए तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से सिर्फ 5,000 लोग कैंपों में हैं।

2010–11 में गृह मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में इनकी आबादी 53,730 थी। 1987 में 45,000 अन्य चकमा लोगों ने बांग्लादेश से त्रिपुरा में प्रवेश किया था।

1947 में भारत विभाजन के बाद चटगांव को पूर्वी पाकिस्तान को सौंपे जाने के विरोध ा में चकमा बुद्ध आज भी श्चकमा ब्लैक डेश का आयोजन करते हैं। यही नहीं 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो वह उसका हिस्सा भी नहीं रहना चाहते थे। स्वायत्ता के लिए उन्होंने शांति वाहिनी के नाम से सशस्त्र संघर्ष भी शुरू किया था। बांग्लादेशी सेना से लड़ते हुए ये लोग लगातार भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रवेश करते रहे।

1990 में चकमा लोगों से शेख हसीना सरकार ने शांति वार्ता की थी और उन्हें जनजाति का दर्जा दिया था। हालांकि अब भी चकमा वहां उ त्पीड़न के डर से भारत में ही बने रहना चाहते हैं।

2005 में चुनाव आयोग ने चकमा और हजोंग शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया था। अरुणाचल की मतदाता सूचियों में करीब 1,000 से ज्यादा चकमा लोगों के नाम शामिल हैं।

करेगी. सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जस्टिस चन्द्रचूड़ ने डिजिटल कम्पनियों द्वारा डेटा कलेक्शन पर चिंता जताई थी. फैसले में जस्टिस सप्रे ने डिजिटल कम्पनियों द्वारा डेटा ट्रान्सफर और प्राइवेसी के उल्लघंन पर चिंता जताई. फैसले में लिखा गया है कि उबर कम्पनी बगैर टैक्सी के, फेसबुक बगैर कंटेन्ट के और अलीबाबा बगैर सामान के ही विश्व की बड़ी कम्पनी बन गई हैं. केएन गोविन्दाचार्य ने सन् 2012 में दिल्ली हाईकोर्ट में डिजिटल कम्पनियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए इन कम्पनियों के ऑफिस और सर्वर्स भारत में स्थापित करने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेसी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने पूर्व जज श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन पर कघनून बनाने के लिए समिति का गठन कर दिया था. तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी दिन से लागू हो गया. प्राइवेसी पर नौ जजों ने सहमति से ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसे तुरंत प्रभाव से सरकार को लागू करना पड़ेगा. इस फैसले के बाद सरकार को इंटरनेट और मोबाइल कम्पनी द्वारा डेटा के गैर–कघनूनी कारोबार पर रोक लगानी होगी, जिससे डिजिटल इंडिया के विस्तार पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं.

फैसले के बाद सरकार के सामने चुनौतियाँ

इस फैसले के बाद सरकार को आधार कानून में बदलाव करने के साथ डेटा प्रोटेक्शन पर जल्द ही कघनून बनाना होगा. डिजिटल इंडिया के व्यापक दौर में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अपनी भूमिका के निर्वहन में विफल रही है. प्राइवेसी के कघनून को लागू करने के लिए सरकार को प्रभावी रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना होगा. इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पिटीशन्स और पीआईएल का दौर आया तो अदालतों में मुकदमों का बोझ और बढ़ जायेगा.

क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है ?

शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था. राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शायद ही बदल पाए. 1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के लिए संसद कघनून नहीं बना सकती. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को अक्टूबर–2015 में निरस्त कर दिया था. प्राइवेसी अब मौलिक अधिकार है जिसे संसद के कघनून द्वारा अब बदलना मुश्किल है.

सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि विकासशील देश में जनता की भलाई के लिए कुछ अभिजात्य लोगों की प्राइवेसी को देशहित में दर–किनार किया जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के सभी 127 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना में खाता खुलवाने की आयु सीमा बढ़कर 65 साल हो गई

राष्ट्रीय पेंशन योजना में खाता खुलवाने की आयु सीमा बढ़कर 65 साल हो गई है। पेंशन क्षेत्र के नियामक पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इसकी घोषणा की। पीएफआरडीए के अध्यक्ष हेमंत कांट्रेक्टर ने बताया कि एनपीएस से जुड़ने की ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 18– 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय हो गया है। इस बारे में पीएफआरडीए बोर्ड ने फैसला ले लिया है और जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना में आयु सीमा बढ़ाए जाने का विकल्प है और आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष तक करने की योजना है। पेंशन में रिफॉर्म करने के सरकार के निर्णय के पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पोर्टेबिलिटी को बढ़ाना या एनपीएस में वृद्धावस्था फंड को स्थांतरित कर इसे ज्यादा आकर्षक और ग्राहकों के लिए आसान बनाना है।

कांट्रेक्टर ने कहा कि उनका उद्देश्य ऐसे सेक्टर के लिए पेंशन योजना शुरू करना है जहां यह उपलब्ध नहीं है। इस समय देश में सिर्फ 15 से 16 फीसदी कामगारों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत में लगभग 85 फीसदी कामगार असंगठित और अनियमित क्षेत्रों में काम करते हैं।

देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 09.09. 2017 को देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का भूमि पूजन किया। लगभग 7000 करोड़ रुपये की यह परियोजना दो वर्षों में मूर्त रूप लेगी। उपराष्ट्रपति ने इसके साथ ही स्मार्ट सिटी परिसर में प्रस्तावित 690 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत वाले अर्बन सिविक टावर, कवेंशन सेंटर तथा झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जुपमी) के बिल्डिंग निर्माण की आधारशिला भी रखी।

इस बीच उन्होंने जहां झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जुटकोल), रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट की लांचिंग की, वहीं स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान का विमोचन भी किया।

रांची स्थिति एचईसी के कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के भूमि पूजन समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्मार्ट सिटी की स्मार्ट परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए स्मार्ट लीडर की जरूरत है। ऐसा लीडर जिसमें क्षमता हो, दूरदर्शिता हो, स्पष्टवादिता हो, जनता के प्रति कमिटमेंट हो। हाई–फाई, कोट–टाई, सूट–बूट नहीं चलेगा।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कि दुनिया आगे बढ़ रही है। फिर हम पीछे क्यों रहें? बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, 24 घंटे बिजली, जलापूर्ति, अच्छी सड़कें, सीवरेज, पार्क, आईटी कनेक्टिविटी, नो व्हीकल जोन, स्मार्ट मीटरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, पैदल पथ आदि स्मार्ट सिटी की पहचान हैं।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2017 घोषित

खेलो में उत्कृष्टता को पहचानने और खिलाडियों को पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता बनाने के लिए प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल विकास में जीवन–भर योगदान के लिए ध्यान चंद पुरस्कार दिया जाता है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की. पैरा एथलीट देवेंद्र और हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

29 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति भवन में विशेष आयोजन समारोह में पुरस्कार विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया.

राजीव गांधी खेल रत्न 2017

1.श्री देवेन्द्र पैरा एथलीट
2. श्री सरदार सिंह हॉकी

द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017

1. स्वर्गीय डॉ आर गांधी एथलेटिक्स
2. श्री हीरा नंद कटारिया कबड्डी
3. श्री जी एस एस वी प्रसाद बैडमिंटन
4. श्री बृज भूषण मोहंती मुक्केबाजी
5. श्री पी.ए. राफेल हॉकी
6. श्री संजय चक्रवर्ती शूटिंग
7. श्री रोशन लाल कुश्ती

चेनानी–नाशरी सुरंग

चेनानी–नाशरी सुरंग जिसे पत्नीटॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पुनः निर्धारण से पूर्व नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए) पर स्थित एक सड़क सुरंग है। इसका कार्य वर्ष 2011 में आरम्भ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया।

यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है

जिसकी लंबाई 9.28 कि.मी. (5.8 मील) है। सुरंग बनाने पर मूल अनुमानित लागत 2,520 करोड़ (यूएस + 367.92 मिलियन) थी लेकिन परिवर्धित करने में कुल 3,720 करोड़ (यूएस + 543.12 मिलियन) खर्च हुये। मुख्य सुरंग का व्यास 13 मीटर है, जबकि समानांतर निकासी सुरंग का व्यास 6 मीटर है। मुख्य और निकासी सुरंगों में 29 स्थानों पर पार मार्ग बनाये गये हैं जो हर 300 मीटर की दूरी पर स्थिति हैं। यह देश की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत सुरंग प्रणाली वाली सुरंग है।

सुरंग की सहायता से जम्मू और श्रीनगर के मध्य दूरी 30.11 कि.मी. (18.7 मील) रह गयी और यात्रा समय में दो घण्टे की कटौती हो गयी। पत्नीटॉप पर सर्दियों में बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बाधा उत्पन्न होती थी तथा प्रत्येक शीतकाल में कई बार वाहनों की लम्बी कतार के कारण भी बाधा उत्पन्न होती थी – कई बार कई दिनों तक कतार में रहना पड़ता था। सुरंग पत्नीटॉप, कुद और बटोत को उपमार्गों से जोड़ती है जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सर्दियों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया है।

1. सुरंग निचले हिमालय परास में स्थिति है जिसकी ऊँचाई 1200 मीटर है।
2. चेनानी–नाशरी सुरंग को आस्ट्रिया की नई सुरंग प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के कई प्रावधान हैं। सभी का संचालन एक सॉफ्टवेयर से होता है।
3. इस परियोजना को बनाने का टेंडर एनएचआई के साथ आईएल एंड एफएस को मिला था।
4. यह सुरंग जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग को चार लेन का करने की परियोजना का हिस्सा है। जम्मू–श्रीनगर के बीच यात्रा की अवधि घटाने के लिए बारह ऐसी ही और सुरंग परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है।
5. यह सुरंग ऊधमपुर जिले के चेनानी और रामबन जिले के नाशरी के बीच की 41 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 10.89 किलोमीटर कर देगी और यह फासला महज दस मिनट में पार कर लिया जाएगा। अभी इसमें ढाई घंटे लगते हैं।
6. जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग को राज्य की जीवन रेखा माना जाता है।
7. सभी 12 सुरंगों का निर्माण पूरा होने के बाद जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की 293 किलोमीटर की दूरी में से 62 किलोमीटर घट जाएंगे। यह 231 किलोमीटर की दूरी चार–साढ़े चार घंटे में तय कर ली जाएगी।
8. इस सुरंग की बेहद खास बात हर 150 मीटर पर एक आपातकालीन एसओएस कॉल बॉक्स और बाहर निकलने के लिए बचाव के रास्ते का होना है। इस रास्ते से होकर मुसाफिर सुरक्षा सुरंग तक जा सकेंगे जो इस मुख्य सुरंग के समानांतर बनाई गई है।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने फैसला किया है कि जम्मू एवं कश्मीर में लेह और श्रीनगर के बीच बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी जोजी ला सुरंग को इसी तकनीक से बनाया जाएगा।

वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017

यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017 में नॉर्वे को दुनिया का सबसे खुशी देश करार दिया गया है। यह पिछले साल चौथी रैंक पर था। इस बार यह डेनमार्क को पीछे छोड़ नंबर वन बन गया है। वहीं, 155 देशों की लिस्ट में चीन 79वें, पाकिस्तान 80वें और भारत 122वें नंबर पर है। यानी यूएन यह मानता है कि भारतीयों से ज्यादा पाकिस्तानी खुश रहते हैं। बता दें कि पिछली बार भारत इस लिस्ट में 118वें नंबर पर था। इस बार वह रैंक में चार पायदान और पीछे हो गया है।

वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट 2017 तैयार करने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के डायरेक्टर जैफरी एस. ने कहा कि खुश देश वो हैं जहां खुशहाली, सोसायटी में आपसी भरोसा, लोगों के बीच बराबरी और सरकार पर भरोसा ज्यादा है और इन सभी के बीच अच्छा बैलेंस है।

इस सालाना रिपोर्ट का मकसद सरकारों और सिविल सोसायटी को खुशहाली के बेहतर तरीके बताना हैं।देशों के हैप्पीनेस इंडेक्स को वहां प्रति व्यक्ति जीडीपी, अच्छी लाइफ एक्सपेंटेंसी, फ्रीडम, सोशल सपोर्ट, उदारता और सरकार या बिजनेस में जीरो करप्शन के पैमाने पर आंका गया।

टॉप–10 में शामिल देश

1	नॉर्वे
2	डेनमार्क
3	आईसलैंड
4	स्विट्जरलैंड
5	फिनलैंड
6	नीदरलैंड
7	कैनेडा
8	न्यूजीलैंड
9	ऑस्ट्रेलिया
10	स्वीडन
79	चीन
80	पाकिस्तान
122	भारत

2012 से हर साल आ रही इस रिपोर्ट में 2016 में डेनमार्क नंबर वन और नॉर्वे नंबर 4 पर था। इस बार वह नंबर–1 हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्वे ने अपने देश में तेल की कम कीमतों के बावजूद नंबर–1 रैंक हासिल की है। यह देश सिर्फ ऑयल वैल्थ के चलते सबसे ज्यादा हैप्पी नहीं है। वह ऑयल को काफी धीरे–धीरे प्रोड्यूस कर रहा है। मौजूदा दौर की बजाय फ्यूचर की चीजों पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है।

नॉर्वे में लोगों के बीच आपसी भरोसे का भाव है। ज्यादातर लोग एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। वहां के लोगों में उदारता है। देश में गुड गवर्नेंस है। सब–सहारा अफ्रीका में आने वाले देश जैसे सीरिया और यमन 155 देशों की लिस्ट में सबसे कम खुश हैं। हैप्पीनेस के 6 पैमानों पर ये देश सबसे कमजोर हैं।

मेधा

आजादी के करीब 70 साल बाद भारत की पहली मेड इन इंडिया ट्रेन 18.03.2017 से चलनी शुरू. रेलमंत्री सुरेश प्रभु मुंबई में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. भारत की स्वदेशी ट्रेन का नाम श्मेधाश रखा गया है. अपनी पहली यात्रा में मेधा ट्रेन ने मुंबई के चर्चगेट से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) तक की यात्रा की.

इससे पहले श्मेधाश ट्रेन का कई चरण में सफल ट्रायल किया जा चुका है. इस ट्रेन को कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी (सीआरएस) की स्वीकृति मिल चुकी है.

भारत की स्वदेशी ट्रेन में कई ऐसी खूबियां हैं जो उसे दुनिया के कई ट्रेनों से उसे अगल बनाती है. इस ट्रेन में एक साथ 6,050 यात्री यात्रा कर सकते हैं. इसमें 1,168 सीटे हैं. इस ट्रेन की स्पीड 110 किमी प्रति घंटा है.

इस ट्रेन में फ्रेश एयर कूलिंग क्षमता 16,000 प्रति घंटा मीटर क्यूबिक है. रिजेनरेटड ब्रेकिंग सिस्टम युक्त यह रेक 30 से 35 प्रतिशत बिजली परिचालन के दौरान बचा सकती है. रेलवे अधिकारी के मुताबिक मेड–इन–इंडिया ट्रेन श्मेधाश को बनाने में लगभग 43.23 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. जबकि विदेश से खरीदी जाने वाली बॉम्बार्डियर ट्रेन की कीमत 44.36 करोड़ रुपए है.

मेक इन इंडिया के तहत देश की पहली स्वदेशी लोकल श्मेधाश हैदराबाद मेधा सर्वो ड्राइव्स फर्म की ओर से प्रायोजित है और चेन्नई कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है. वर्तमान में मध्य और पश्चिम रेल पर परिचालित होने वाली लोकल चौन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में तैयार होती है. इन लोकल ट्रेनों में इलेक्ट्रिक तकनीकी समेत अन्य तकनीकी संबंधी काम सीमेंस और बॉम्बार्डियर कंपनियों की देख रेख में होता है. ये कंपनियां विदेशी हैं.

भारत और विश्व

ब्रिटेन की संसद ने पारित किया ब्रेग्जिट विधेयक

ब्रिटेन की संसद ने 'ब्रेग्जिट विधेयक' पारित करते हुए प्रधानमंत्री टेरीजा मे के लिए यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकासी पर बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने 13.03.2017 को हाउस ऑफ लॉर्डस के संशोधनों को 335–287 मतों के अंतर से खारिज कर दिया था। इन संशोधनों में सरकार से कहा गया था कि वह ब्रेग्जिट वार्ताओं की शुरूआत के तीन माह के भीतर यूरोपीय संघ के नागरिकों की स्थिति की सुरक्षा करे। उन्होंने ब्रेग्जिट के समझौते पर संसद में अर्थपूर्ण मतदान कराए जाने के आह्वान को भी 331–286 मतों के अंतर से खारिज कर दिया।

इसका अर्थ यह हुआ कि यूरोपीय संघ (निकासी की अधिसूचना) विधेयक बिना किसी बदलाव के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया। इसके बाद यह हाउस ऑफ लॉर्डस में बिना किसी संशोधन के पारित हो गया। वहां इसके पक्ष में 274 और विरोध में 118 मत पड़े। इससे निकासी की शर्तों पर संसद के पास वीटो का अधिकार के मुद्दे पर अब इसे कॉमन्स में दोबारा चुनौती नहीं दी जा सकती। हाउस ऑफ लॉर्डस पहले ही इस बात पर सहमत हो गया था कि यूरोपीय संघ के नागरिकों के दर्जे के मुद्दे गारंटी को विधेयक में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हें सांसदों ने खारिज कर दिया था। ऐसी उम्मीद है कि विधेयक को कानून बनाने के लिए अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से शाही मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद एलिजाबेथ लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को इस सप्ताह किसी भी समय सैद्धांतिक तौर पर शुरू कर सकती हैं। हालांकि इस बात के संकेत कम हैं कि वह इस माह के अंत तक बातचीत शुरू कर पाएं। विपक्षी लेबर पार्टी ने पहले मे से अपील की थी कि वह 'वाकई अहम' लॉर्डस संशोधनों को बरकरार रखने पर विचार करें।

मधेसी

नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेस कहते हैं और यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं और तराई में वास करने वाले इन नेपाली लोगों को तराईबासी भी कहते हैं। मधेश शब्द मध्यदेश का अपभ्रंश है। मैथिली, थारु, अवधी, भोजपुरी और अन्य भाषाएँ (जो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बोली जाती है) बोलने वाले लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों जैसे दिखते हैं और जिनकी संस्कृति और रीति–रिवाज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगो जैसी है लेकिन जो नेपाली हैं, वो लोग मधेसी कहलाते हैं।

मधेसी मुल के नेपाली और भारत के बिहारी या उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों में कुछ भी असमानता नहीं है, अन्तर केवल यह है कि मधेसी नेपाली हें जो सीमा के उस पार रहते हैं।

प्राचीन समय में मिथिला और अवध स्वतंत्र राज्यस थें। 17वीं सदी में जब गोर्खा के राजा नेपाल एकीकरण कर रहें थें तब मिथिला और अवध के छोटे से भू–भाग पर नेपाल का कब्जा हो गया बाद में अंग्रेजों ने मिथिला और अवध के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और भारत मे गाभा।

भू–विवाद के कारण 1814–16 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नेपाल–अंग्रेज युद्ध हुआ और युद्ध दो वर्षों तक चला अन्त में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधी हुई जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। सुगौली संधि के अनुसार नेपाल ने मेची नदी से पुर्व का सारा भू–भाग, घाघरा नदी से पश्चिम का सारा भू–भाग और लगभग सम्पूर्ण तराई भू–भाग अंग्रेजों को सौपना पड़ा। बाद में 1857 में लखनऊ विद्रोह में अंग्रेजों कि मदद करने के एवज में अंग्रेजों ने दक्षिण का सम्पूर्ण तराई भू–भाग नेपाल को वापस लौटा दिया। वापस किये गये इस भू–भाग में मिथिला और अवध के लोग रह रहे थें। यह भू–भाग जब नेपाल में सम्मिलित किया गया तो नेपाल के लोग इस भू–भाग को नया देश या मध्य–देश कहने लगें क्योकि यह भू–भाग नेपाल और भारत के मध्य में था। मध्य–देश का अपभ्रंश मधेश हो गया और मध्य–देशी से मधेशी हो गया।

नेपाल के नए संविधान में मधेसी दोयम दर्जे के नागरिक

संविधान तैयार करना किसी भी देश का अपना अधिकार है और नेपाल ने भी यही किया है। लेकिन क्या नेपाल ने अपने देश की लगभग आधी आबादी यानी मधेसियों को संविधान में पूरा प्रश्रय दिया है? अगर नेपाल के संविधान के कुछ हिस्सों को देखें तो यह साफ हो जाता है कि इसके कई प्रावधान मधेसियों को वहां दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से तराई के मधेसी बहुल हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस वजह से जो हिंसा फैली है उसमें काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

जानकारों के मुताबिक नेपाल के पांच विवादित जिलों कांचीपुर, कैइलाली, सुनसरी, झापा और मोरांग को इसके पड़ोसी जिलों में मिलाने का रास्ता तैयार किया गया है। इन पांच जिलों में पहाड़ी लोगों की संख्या ज्यादा है और इन्हें पड़ोस के उन जिलों में मिलाने की तैयारी है जहां मधेसियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन एकीकरण के बाद इन जिलों में पहाडियों का जनसंख्या अनुपात ज्यादा हो जाएगा। मधेसियों को इस बात का भी गुस्सा है कि किस तरह से संविधान बनाने के लिए गठित अंतरिम समिति की अहम सिफारिशों को खारिज कर दिया गया है। जैसे अंतरिम समिति ने धारा 63 (3) में मधेसियों को उनकी आबादी के हिसाब से संसद में 50 फीसद हिस्सा देने का प्रस्ताव किया गया था। अब उसे हटा दिया गया है। इसी तरह से मधेशियों को सही प्रतिनिधित्व देने संबंधी धारा (21) में भी काफी बदलाव किया गया है।संविधान की धारा 283 में इस बात का साफ तौर पर प्रावधान है कि देश के शीर्ष पदों मसलन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद के अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष आदि के पद पर सिर्फ नेपालवंशी ही स्थापित हो सकते हैं।

इसका साफ मतलब हुआ कि जन्म से नेपाल की नागरिकता लेने वाला या प्राकृतिक तौर पर नागरिक बनने वाले मधेसी इन पदों पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अंतरिम संविधान में हर दस वर्ष पर संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन करने की भी भी बात थी जिसे बढ़ा कर 20 वर्ष कर दिया गया है। मधेसियों की मांग है कि इसे 10 वर्ष ही रहने दिया जाए।विदेशी महिलाओं से शादी के बाद उन्हें नागरिकता देने के मामले पर किए गए प्रावधान भी मधेसियों के हितों के खिलाफ है। चूंकि बड़ी संख्या में मधेसियों की शादी अभी भी भारत में होती है और संविधान में नागरिकता के लिए अलग से आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। मधेसियों का कहना है कि शादी होने पर प्राकृतिक तौर पर नेपाल की नागरिकता देने का प्रावधान होना चाहिए।

अर्थव्यवस्था/वाणिज्य

प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण आवास योजना– 'ग्रामीण' का क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना 'ग्रामीण' के क्रियान्वयन को अनुमति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण–शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्षों में 81975 रुपये खर्च होंगे।

यह प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 के कालखंड में एक करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी। मकानों की कीमत केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी।

क. प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण आवास योजना– ग्रामीण का क्रियान्वयन।

ख. ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ आवासों के निर्माण के लिए 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्षों में मदद प्रदान की जाएगी।

ग. समतल क्षेत्रों में प्रति एकक 1,20,000 तक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 तक सहायता में बढ़ोतरी।

घ. 21,975 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से की जाएगी।

ड. लाभान्वितों की पहचान के लिए सामाजिक–आर्थिक–जातीय जनगणना–2011 का उपयोग।

च. परियोजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता हेतु नेशनल टेकनिकल सपोर्ट एजेंसी का गठन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंजूरी दी जो किसानों के कल्याण के लिए लीक से हटकर एक अहम योजना है। किसान हितैषी सरकार का नया तोहफा –

(1) लोहिड़ी, पोंगल एवं बीहू जैसे त्यौहारों के शुभ अवसर पर किसान हितैषी सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। यह योजना खरीफ 2016 से लागू है।

(2) किसानों के लिए बीमा योजनाएं समय–समय पर बनती रहीं हैं, किंतु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत हो सका है।

(3) सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में बेहतर है।

(4) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1.	खरीफ	2.0 प्रतिशत
2.	रबी	1.5 प्रतिशत
3.	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें	5 प्रतिशत

(5) वर्ष 2010 से प्रभावी डवकपपिमक NAIS में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाती थी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में धान की फसल के लिए 22 प्रतिशत Actuarial Premium था। किसान को 30 हजार रुपए के Sum Insured पर कैप के कारण मात्र 900 रुपए और सरकार को 2400 रुपए प्रीमियम देना पड़ता था। किंतु शत–प्रतिशत नुकसान की दशा में भी किसान को मात्र 15 हजार रुपए की दावा राशि प्राप्त होती।

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 143वां स्थान

आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143वें स्थान पर रहा है। एक अमेरिकी शोध संस्थान 'द हेरिटेज फाउंडेशन' की **'इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम'** में भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। इसका प्रमुख कारण भारत में बाजार को ध्यान में रखकर किए गए आर्थिक सुधारों से होने वाली प्रगति का 'असमान' होना बताया गया है।

इस रपट में कहा गया है कि भारत में पिछले पांच साल में औसतन सात प्रतिशत की दर से सतत वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि नीतियों में गहरे तक नहीं समाई है जिससे कि आर्थिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके। इस कंजरवेटिव राजनीतिक विचारधारा के शोध समूह की रपट में भारत को 'अधिकांशतया गैर–खुली' अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि भारत में बाजार आधारित सुधारों से हुई प्रगति 'असमान' रही है। इसमें कहा गया है कि राज्य ने लोक उपक्रमों के माध्यम से कई क्षेत्रों में 'अपनी एक व्यापक उपस्थिति बनाए रखी है'। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक और भारी–भरकम नियामकीय वातावरण से उद्यमिता हतोत्साहित होती है। यदि यह ना हो तो निजी क्षेत्र का व्यापक प्रसार किया जा सकता है। इस सूचकांक में भारत ने कुल 52.6 अंक हासिल किए जो पिछले साल के मुकाबले 3.6 अंक कम है।

पिछले साल इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 123 थी। इस सूचकांक में हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत से नीचे अफगानिस्तान 163 और मालदीव 157वें स्थान पर हैं, जबकि इस सूचकांक में नेपाल का स्थान 125, श्रीलंका का 112, पाकिस्तान का 141, भूटान का 107 और बांग्लादेश का 128 है। चीन ने इस सूचकांक में 57.4 अंक हासिल किए जो पिछले साल के मुकाबले 5.4 अंक ज्यादा है। इस साल उसका स्थान 111 वां रहा है। अमेरिका 75.1 अंक हासिल कर 17वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में वैश्विक औसत 60.9 अंक रहा जो पिछले 23 साल में रिकॉर्ड उच्चस्तर है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक ही रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया है। इन उपग्रहों में भारत का पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भी शामिल है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। किसी एकल मिशन के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पीएसएलवी–सी37 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सुबह नौ बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरी।

इसने सबसे पहले काटरेसैट–2 श्रेणी के उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया और इसके बाद शेष 103 नैनो उपग्रहों को 30 मिनट में प्रवेश कराया गया। इनमें 96 उपग्रह अमेरिका के थे। अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने पर मिशन कंट्रोल सेंटर के वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने घोषणा की, ''सभी 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कराया गया। इसरो के पूरे दल को उनके द्वारा किए गए इस अद्भुत काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।'' एक बार में सबसे ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित करने का श्रेय अब तक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के पास था। उसने एक बार में 37 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था। इसरो ने जून 2015 में एक मिशन में 23 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो दल को बधाई दी। आज के इस जटिल मिशन में 28 घंटे की उल्टी गिनती पूरी होने के बाद पीएसएलवी–सी37 ने 714 किलोग्राम के काटरेसैट–2 श्रृंखला के उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया। इसके बाद उसने इसरो के नैनो उपग्रहों– आईएनएस–1ए और आईएनएस–1बी को 505 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित ध्रुवीय सौर स्थतिक कक्षा में प्रवेश कराया।

आने वाले समय में भारत सैटेलाइट्स मेकिंग की एक बड़ी मार्केट बन सकता है। सैटेलाइट वेंचर वनवेब की इंडियन फर्म भारती के साथ साझेदारी है। यह लगभग 648 छोटे सैटेलाइट्स बनाएगा जिससे दुनियाभर में तेज इंटरनेट स्पीड पहुंचा सके। वहीं यह दूसरा मौका है जब प्लैनेट लैब्स ने पीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल अपनी 88 छोटी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने के लिए इस्तेमाल की हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसरो का यह लॉन्च ऐसे समय में आया है जब छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वालों की दुनियाभर में कमी हो रही है और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में प्राइवेट सैटेलाइट इंडस्ट्री में तेजी है। दरअसल इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल मौसम की जानकारी, जीपीएस सिस्टम और इंटरनेट को तेज करने के लिए किया जाएगा। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि पीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल लगभग 225 सैटेलाइट लॉन्च में किया गया है जिनमें से 179 विदेशी ग्राहकों की सैटेलाइट हैं।

भारत का अंतरिक्ष का सफर

- इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च (इन्कोस्पार) ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1962 में की थी।
- इन्कोस्पार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत काम करती थी।
- यह बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) में बदल गई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।

54 साल पहले लॉन्चिंग

- भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था।
- यह एक नाइक अपाचे रॉकेट था, जिसे अमेरिका से लिया गया था।
- इसे सिर्फ लॉन्चिंग की ताकत परखने के लिए छोड़ा गया था।58 साल पहले पहला रॉकेट
- भारत में बना पहला रॉकेट रोहिणी
- 75 था, इसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत परखने के लिए था।

42 साल पहले पहला सैटेलाइट

- आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था।
- 360 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट का नाम प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था।
- आर्यभट्ट को मैसेज भेजने के लिए बहुत बड़े एंटेना का इस्तेमाल किया जाता था।

38 साल पहले पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट

- 7 जून 1979 को इसरो ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर–1 लॉन्च किया था।
- यह भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था।
- भास्कर–1 की भेजी फोटो का इस्तेमाल जंगल, पानी और समुद्र के बारे में जानकारी जुटाई जाती थी।

24 साल पहले लॉन्च हुआ *PSLV*

- पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (प्स्ट) इसरो का पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है।
- इसने पहले उड़ान 20 सितंबर 1993 को भरी थी। हालांकि, यह लॉन्चिंग नाकाम रही थी।
- यह इसरो का अभी तक का सबसे कामयाब लॉन्च व्हीकल है।
- PSLV ने अब तक 39 उड़ान भरी हैं, जिनमें से 37 पूरी तरह कामयाब रही हैं।

ये तीन कामयाबी जिन्होंने दुनिया को चौंकाया

चंद्रयान–1

- इसरो ने इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। इसने 30 अगस्त 2009 तक काम किया।
- इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर मौजूदगी दर्ज कराने वाला छठा देश बन गया।
- इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, चीन और यूरोप अपने स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेज चुके हैं।

मंगलयान–1

- 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया।
- इस ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश बना।
- इस मिशन की सबसे खास बात ये रही कि इसरो ने यह कामयाबी पहली ही कोशिश में हासिल की।
- इसके अलावा अमेरिका और रूस के मिशन की तुलना में इसकी लागत बेहद कम थी। इसे सिर्फ 400 करोड़ रुपए में पूरा किया गया।

104 सैटेलाइट्स एकसाथ लॉन्च किए

- 15 फरवरी 2017 को भारत ने एकसाथ 104 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजकर रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
- रूस के नाम एक बार में 37 सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड था।
- इससे पहले भारत एक बार में 23 सैटेलाइट्स तक भेज चुका था।

आगे क्या है इसरो की प्लानिंग?

- इसरो आने वाले वक्त में सन, वीनस, जूपिटर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है।
- भारत मून और मार्स पर दोबारा अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है।

क्या है रैंजमवेयर साइबर अटैक ?

रैंजमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर वाइरस है जिसको हैकर्स के द्वारा आपके डेस्कटॉप में किसी ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजा जाता है. इस वायरस में इतना पॉवर होती है कि यह आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को लॉक कर देता है. आप इसके बाद यूजर चाह कर भी इसे अनलॉक नहीं कर पायेगे. लॉक होने के स्थिति में आप अपने सिस्टम को हैकर्स को पैसे पेय करने के बाद भी अनलॉक कर पायेगे या नहीं इस बात पर संदेह है. इस तरीके का यूज कर हैकर लोगो से पैसे निकलवा लेते है. वैसे रैंजमवेयर वायरस का सबसे ज्यादा अटैक विंडोज XP पर देखा गया है. मास्को की कंपनी के जारी किये गए अपडेट पर ध्यान दे तो यह वायरस 2,18,624 रैंजमवेयर फिलो की पहचान की गयी है.

रक्षा/प्रतिरक्षा

जीबीयू–43

अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा बम गिराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिका ने जो बम जीबीयू–43 अफगानिस्तान पर गिराया है, वो इतना खतरनाक है कि उसके सवा तीन किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक हो जाएगा. इस बम को नानगरहार प्रांत के अचिन जिले में एक सुरंगनुमा इमारत पर गिराया गया है. अफगानिस्तान में अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एक बयान में यह जानकारी दी. ये हमला वहां के समय के मुताबिक शाम 7.32 बजे हुआ. ये हमला भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले की तरह ही अमेरिकी सरकार के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है. अगस्त 6 और अगस्त 9, 1945 को हुए इस हमले में 2 लाख 46 के करीब लोग मारे गए थे. अमेरिकी वायु सेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम ष्लिटिल बॉय गिराया था. उसके तीन दिनों बाद अमरीका ने फिर नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया. हालांकि जीबीयू–43 परमाणु बमों की श्रेणी में नहीं आता है.

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि उसने पूर्वी अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ठिकानों पर सबसे बड़ा और खतरनाक जीबीयू–43 बम गिराया है. इस बम को सबसे शक्तिशाली बम बताया जाता है. पेंटागन के प्रवक्ता ने बताया कि पहली बार इस बम का प्रयोग किया गया है और इसे MC–130 एयरक्राफ्ट से गिराया गया.

21600 पौंड वजनी (तकरीबन 10 हजार किलो) इस बम का नाम जीबीयू–43 है. इसे मदर ऑफ आल बम भी कहा जाता है. इस तरह का बम पूरी दुनिया में सिर्फ 15 है. सवा तीन किलोमीटर के दायरे में यह सब कुछ खाक कर देता है. यह बम जीपीएस से संचालित होता है. ऐसे में इसके निशाना चूकने का कोई सवाल ही नहीं. जीबीयू–43 बम से 11 टन TNT के बराबर धमाका होता है. इस बम को बनाने में तकरीबन दो हजार करोड़ रुपये का

इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण

11 फरवरी 2017 को भारत ने ओडिशा के तट से अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया और द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि ा हासिल की। इस इंटरसेप्टर को आईटीआर के अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से सुबह सात बजकर 45 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया।

''पीडीवी नामक यह अभियान पृथ्वी के वायुमंडल से 50 किमी ऊपर बाहरी वायुमंडल में स्थित लक्ष्यों के लिए है।''

पीडीवी इंटरसेप्टर और दो चरणों वाली लक्ष्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। लक्ष्य को दरअसल 2000 किमी से अधिक दूरी से आती शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर विकसित किया। इसे बंगाल की खाड़ी में एक पोत से दागा गया।एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान कर ली। रडार से मिले आंकड़ों की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क ने आ रही बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग पता लगा लिया। पीडीवी को पूरी तरह तैयार रखा गया था। कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इसे छोड़ दिया गया। यह अहम दिशासूचक प्रणालियों की मदद से अवरोधन बिंदू तक पहुंच गई। सभी कार्यों का निरीक्षण विभिन्न स्थानों पर स्थित टेलीमीट्री, रेंज स्टेशनों ने तत्काल आधार पर किया।

उन्नत तकनीकी वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो बैलेस्टिक मिसाइल वाले दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए बड़ा हथियार बनेगी और भारत के सुरक्षा कवच का काम करेगी। खासकर, पाकिस्तान और चीन के हमलों का जवाब देने के लिए यह मिसाइल भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। इस इंटरसेप्टर को आईटीआर के अब्दुल कलाम द्वीप श्व्हीलर द्वीपश से सुबह सात बजकर 45 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि पीडीवी नामक यह अभियान पृथ्वी के वायुमंडल से 50 किमी ऊपर बाहरी वायुमंडल में स्थित लक्ष्यों के लिए है। उन्होंने कहा, पीडीवी इंटरसेप्टर और दो चरणों वाली लक्ष्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ।खर्च आता है.

पुरस्कार/सम्मान

नोबेल पुरस्कार 2017

नोबेल शांति पुरस्कार 2017

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ***'इंटरनेशनल कैम्पेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स'*** (आईकैन) को दिया गया है. नोबेल कमेटी की प्रमुख बेरिट रेइस–एंडरसन ने कहा कि परमाणु हथियारों पर रोक की संधि की आईकैन की कोशिशों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है. उन्होंने उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए कहा, *''हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खघ्तरा पहले से कहीं ज्यादा है.''* उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न देशों से एटमी हथियार खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने की अपील की है.

इंटरनेशनल कैम्पेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी आईकैन सौ से ज्यादा देशों में काम करने गैर सरकारी संस्थाओं का समूह है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। 30 अप्रैल, 2007 को विएना में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया। ***स्वीडन की बीट्रीस फिन्ह इसकी प्रमुख*** हैं।

- 101 देशों के 468 संगठन जुड़े हैं इससे
- स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं मुख्यालय
- भारत के तीन संगठन जुड़े हैं इससे :

1. इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलेपमेंट
2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, डिसआर्नामेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन
3. पापुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर

जुलाई में 122 देशों ने परमाणु हथियारों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संधि को मंजूरी दी थी। इसमें अमरीका, रूस, चीन, ब्रिटेन शामिल थे और फ्रांस इस वार्ता से बाहर रहा था।

शांति का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो दो देशों के बीच भाई–चारे को बढ़ावा देते हैं या फिर समाज के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं जिससे लोगों को नई जिंदगी मिलती है। भारत में ***मदर टेरेसा*** *और* ***कैलाश सत्यार्थी*** *को शांति पुरस्कार दिया जा चुका है जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अहम योगदान दिया। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में जबकि अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं।*

शांति में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- नोबेल शांति पुरस्कार को पांच व्यक्तियों की एक समिति द्वारा सम्मानित किया जाता है जिन्हें नॉर्वेजियन स्टॉर्टिंग (नॉर्वे की संसद) द्वारा चुना जाता है.
- 1901–2017 के बीच 98 नोबेल शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
- अब तक 16 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
- 1 शांति पुरस्कार विजेता, ले डुक थो, ने नोबेल शांति पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था.
- 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले *मलाला यूसुफजई (17) सबसे कम उम्र* के हैं.

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017

ब्रिटिश लेखक ***काज्शुओ इशिगूरो*** को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा. उनका सबसे मशहूर उपन्यासों ***'द रिमेन्स ऑफ द डे'*** और ***'नेवर लेट मी गो'*** पर क्रमशः 1993 और 2010 में फिल्में भी बनाई गईं. नोबेल अकादमी ने उनकी प्रशंसा में उनका परिचय इस तरह दिया है, *''जिन्होंने शानदार भावनात्मक उपन्यासों में दुनिया से हमारे संपर्क से जुड़े हमारे भ्रामक अर्थों के नीचे की खाई को उजागर किया है.''* 62 वर्षीय काज्शुओ ने कहा है कि नोबेल पुरस्कार **'सुखद आश्चर्य'** की तरह है.

काज्शुओ इशिगूरो का जन्म जापान के नागासाकी में 1954 में हुआ था. इसी शहर पर 9 साल पहले 1945 में अमरीका ने परमाणु बम गिराया था. बाद में काज्शुओ अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए. उनके पिता को सरे में समुद्र विज्ञानी की नौकरी मिली थी. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केंट से अंग्रेजी और फिलॉसफी की पढ़ाई की. पूर्वी एंगलिया से उन्होंने रचनात्मक लेखन में मास्टर्स किया, जहां मैल्कॉम ब्रैडबरी और एंजेला कार्टर उनके शिक्षक थे. उन्होंने कुल आठ किताबें लिखी हैं, जिनका 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है. उनकी थीसिस ही उनका पहला उपन्यास बनी. 1982 में छपी इस किताब का नाम था *'अ पेल व्यू ऑफ हिल्स'* 1989 में उन्हें ***'द रिमेन्स ऑफ द डे' के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार*** दिया गया. 1995 में उन्हें महारानी की ओर से *'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर'* का सम्मान दिया गया.

साहित्य में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है.
- साहित्य में 1901–2017 के बीच 110 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
- अब तक 14 महिलाओं को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
- सबसे कम उम्र के साहित्यिक विजेता, 41 वर्षीय रुडयार्ड किपलिंग, द जंगल बुक के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं.
- डोरिस लेसिंग को जब 2007 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो वे 88 वर्ष की सबसे अधिक आयु की साहित्यिक विजेता थी.

चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2017

अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों ***जैफ्री सी हाल, माइकल रोसबाश*** तथा ***माइकल डब्ल्यू यंग*** को मानव शरीर की ***''आंतरिक जैविक घड़ी''*** विषय पर किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए इस साल के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ***'आंतरिक जैविक घड़ी' को सर्केडियन रिदम के नाम से जाना जाता*** है। नोबेल असेम्बली ने कहा है, "उनकी खोजों में इस बात की व्याख्या की गई है कि पौधे, जानवर और इंसान किस प्रकार अपनी आंतरिक जैविक घड़ी के अनुरूप खुद को ढालते हैं

पुलित्जर पुरस्कार 2017

पुलित्जर पुरस्कार समिति ने 10 अप्रैल 2017 को 101वें पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने सर्वाधिक 3 पुरस्कार झटके। द न्यूयॉर्क डेली न्यूज और प्रोपब्लिका को संयुक्त रूप से समाजसेवी पत्रकारिता के लिए साल 2017 का पुरस्कार दिया गया है। इस बार 'द डेली न्यूज' और 'प्रोपब्लिका' को साझा तौर पर समाजसेवी पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार मिला है। दरअसल, इन दोनों समाचार समूहों ने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग पर एक साझा सीरीज की थी, जिसमें दशकों पुराने कानून का दुरुपयोग कर आम लोगों को उनके घरों और कारोबार से हटाए जाने की बात थी।

पुलित्जर को अमेरिका का सर्वाधिक सम्मानित पत्रकारिता पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार पहली बार साल 1917 में दिया गया था। इसके बाद 1980 से हर साल इसके लिए अंतिम सूची में शामिल प्रविष्टियों की भी घोषणा की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं को 15 हजार अमेरिकी डॉलर और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

ताकि वे धरती की परिक्रमा के अनुसार अपने को ढाल सकें।"

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कारोलिंसका इंस्टिट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है.
- फिजियोलॉजी या चिकित्सा में 1901 और 2017 के बीच 108 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
- अब तक 12 महिलाओं को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.
- फेडरिक जी. बैंटिंग, 32 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की चिकित्सा नोबेल पुरस्कार विजेता थीं, जिन्हें इंसुलिन की खोज के लिए 1923 में चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
- 87 वर्षीय चिकित्सा पुरस्कार विजेता पीयटन रौस की आयु 87 वर्ष थी जब उन्हें 1966 में ट्यूमर–उत्प्रेरक वायरस की खोज के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2017

इस साल ***जाक दुबोशे*** (स्विटजरलैंड), ***जोआखिम फ्रैंक*** (अमेरिका), ***रिचर्ड हेंडर्सन*** (ब्रिटेन) को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को *बॉयोमालीक्यूल्स के सॉल्यूशन के उच्च संकल्प संरचना के निर्धारण के लिए क्रायो इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी विकसित करने को लेकर सम्मानित किया गया।* जैक्स ड्यूबचित स्विजरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लूसियाना में कार्यरत हैं। फ्रैंक न्यूयार्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं रिचर्ड हेंडरसन कैंब्रिज की एमआरसी लैबोरेटरी ऑफ मॉलीक्यूलर बॉयोलोजी में सेवारत हैं।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा दिया जाता है.
- रसायन विज्ञान में 1901 और 2017 के बीच 109 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.
- अब तक 4 महिलाओं को रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
- 1 व्यक्ति, फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में और 1980 में दो बार रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
- 35 साल की आयु में सबसे कम उम्र के रसायन शास्त्र पुरस्कार विजेता, फ्रेडरिक जलाथिट थे, जिन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
- सबसे अधिक आयु के रसायन विज्ञान पुरस्कार विजेता जॉन बी फेन 85 वर्ष की आयु के थे, जब उन्हें 2002 में रसायन विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2017

वर्ष 2017 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों खगोल वैज्ञानिकों ***बैरी बैरिश, किप थोर्ने*** और ***रेनर वेस*** को *गुरुत्व तरंगों की खोज के लिए इस साल का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार* देने की घोषणा की गयी है। सुविख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके बारे में जानकारी दी थी और ये तरंग रिलेटिबिटी थ्योरी यानी सापेक्षता सिद्धांत का एक बुनियादी निष्कर्ष है। *पुरस्कार विजेता लीगो–विरगो बेधशाला के सदस्य* हैं और इसी बेधशाला से गुरूत्वीय तरंगों का पता लगाया गया था।

कुल 90 लाख क्रोनर पुरस्कार धनराशि में से 45 लाख क्रोनर प्रोफेसर वीज को दिया जायेगा और शेष 45 लाख क्रोनर की रकम में से आधी–आधी राशि बैरिश बैरिश और कीप थॉर्न को मिलेगी।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा दिया जाता है.
- भौतिकी में 1901–2017 के बीच 111 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं.
- अब तक केवल 2 महिलाओं को भौतिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
- 25 वर्ष की उम्र सबसे कम उम्र के भौतिक विज्ञान विजेता लॉरेंस ब्राग की उम्र थी, जब उन्हें अपने पिता के साथ 1915 भौतिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

अर्थशास्त्र का नोबेल 2017

इस बार यह पुरस्कार ***अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड एच थेलर*** को मिला है। *रिचर्ड को यह पुरस्कार बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए दिया गया है।* एकेडमी ने अपने बयान में कहा है, *"नोबेल पुरस्कार के निर्णायक मंडल ने एक बयान में कहा कि थेलर का अध्ययन बताता है कि किस प्रकार सीमित तर्कसंगता, सामाजिक वरीयता और स्व–नियंत्रण की कमी जैसे मानवीय लक्षण किसी व्यक्ति के निर्णय को प्रक्रियागत तौर पर प्रभावित करते हैं और इससे बाजार के लक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है।"* अर्थशास्त्र के नोबेल को अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था।

थालर शिकागो विश्वविद्यालय में बिहेवियरल साइंस और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।

अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्शबैंक पुरस्कार : मुख्य तथ्य

- आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा सम्मानित किया जाता है.
- 1969 के बाद से आर्थिक विज्ञान में 49 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं.
- 2009 में, एक महिला एलिनोर ओस्ट्रम को आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
- आर्थिक विज्ञान में सबसे कम उम्र के विजेता कैनेथ जे. एरो की आयु 51 वर्ष है, जिन्हें 1972 से समान्नित किया गया था.
- लियोनिद हूरविच को जब पुरस्कार प्रदान किया गया था तब वे 90 वर्ष के थे. अब तक के आर्थिक विज्ञान में सबसे अधिक आयु के पुरस्कार विजेता.

89वां ऑस्कर अवॉर्ड

सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म 89वां ऑस्कर अवॉर्ड में ***मूनलाइट*** को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला। हालांकि, फंक्शन में तब ड्रामा क्रिएट हो गया, जब बेस्ट फिल्म के लिए गलती से ला ला लैंड का नाम अनाउंस कर दिया गया। बाद में मूनलाइट को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया।

14 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्म ला ला लैंड ने सबसे ज्यादा 6 अवॉर्ड अपने नाम किए। हालांकि, उसे बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड नहीं मिला। प्रेजेंटर वॉरेन बीटी के हाथ में गलत कैटेगरी वाला एनवेलप आ गया, जिससे वो कुछ देर के लिए चुप हो गए। इसी दौरान उनके साथ खड़ी लेडी प्रेजेंटर ने बेस्ट फिल्म के लिए श्ला ला लैंडश का नाम अनाउंस कर दिया। हालांकि, तभी वहां मौजूद एक प्रोड्यूसर ने इसे गलत बताते हुए सही लिफाफा निकाला और मूनलाइट को बेस्ट फिल्म डिक्लेयर किया। बाद में अवॉर्ड के होस्ट जिमी किमेल ने इस पूरे मामले में अपनी गलती मानी।

लॉस एंजिलिस के डॉल्बी थिएटर में हुए इस अवॉर्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी के लिए केसी एफ्लेक, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड ला ला लैंड की एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला।

- वहीं, बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड ला ला लैंड के ही डेमियन शैजेल को मिला।
- ब्रिघम टेलर की फिल्म द जंगल बुक ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवॉर्ड अपने नाम किया।
- भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार **देव पटेल** ऑस्कर से चूक गए। उन्हें फिल्म लॉयन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। उनकी जगह महर्शेला अली को फिल्म मूनलाइट

के लिए यह अवॉर्ड दिया गया।

- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड फिल्म फेंसेस के लिए विओला डेविस को मिला।
- बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवॉर्ड ईरानी डायरेक्टर असगर फरहदी की द सेल्समैन को मिला।
- वहीं, 14 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई ला ला लैंड ने बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में पहला ऑस्कर अवॉर्ड जीता।
- फिल्म ला ला लैंड के गाने सिटी ऑफ स्टार्स को मिला ऑरिजिनल सॉन्ग अवॉर्ड।
- बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवॉर्ड जूटोपिया को मिला।
- व्हाइट हेल्मेट्स को शॉर्ट सब्जेक्ट डॉक्युमेंट्री का ऑस्कर अवॉर्ड मिला।
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवॉर्ड ला ला लैंड को मिला।
- बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड पाइपर को दिया गया है।
- ऑरिजिनल स्क्रीनप्ले के लिए फिल्म मैनचेस्टर बाई द सी के कीनथ लोनार्गन ने जीता अवॉर्ड।

हॉलीवुड फिल्म लॉयन में देव पटेल के बचपन का रोल निभाने वाले सनी पवार भी ऑस्कर में पहुंचे। सनी की उम्र महज 8 साल है। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और म्यूजिशियन के प्यार की कहानी है ला ला लैंड की कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और म्यूजिशियन पर बेस्ड है। दोनों एक–दूसरे से मिलते हैं और फिर ध्ीरे–धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। फिल्म में एमा स्टोन स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मिया के किरदार में हैं, जो एक कॉफी शॉप में काम करती हैं। वहीं एक्टर रेयान गॉसलिंग म्यूजिशियन सेबस्टियन के रोल में हैं।

गरीब और अश्वेत बच्चे की कहानी है मूनलाइट फिल्म के डायरेक्टर बेरी जेनकिंस हैं। यह एक गरीब और अश्वेत बच्चे के बड़े होने की स्टोरी है। उसे बचपन में कई बार और कई जगहों पर अवॉइड किया जाता है। उसकी मां नशा करती है। बच्चा समलैंगिक यौन–संबंधों को लेकर चल रहे भेदभाव और गरीबी से जूझते हुए बड़ा होता है।ऑस्कर में ओम पुरी को किया गया याद–ऑस्कर सेरेमनी के दौरान दिवंगत बॉलीवुड एक्टर ओम पुरी को ट्रिब्यूट दिया गया।

दरअसल, सेरेमनी के दौरान एक स्पेशल परफॉर्मेंस के तहत उन स्टार्स को श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। चूंकि, ओम पुरी बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के भी स्टार रहे हैं। इसलिए इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हुआ। ओम पुरी ने हॉलीवुड की ईस्ट इज ईस्ट, गांधी, सिटी ऑफ जॉय और वुल्फ जैसी फिल्मों में काम किया है। ओम

59वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड 2017

59वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड की घोषणा हो चुकी है. बेयोंसे को उनकी एल्बम 'लेमोनेड' के लिए सर्वश्रेष्ठ अर्बन कंटेंपररी एल्बम का पुरस्कार मिला. वहीं सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवॉर्ड हैलो, एडेल को मिला. आइए जानते हैं किस सितारे ने जीता कौन–सा अवॉर्ड.

विजेताओं के नाम

- सॉन्ग ऑफ द ईयर : हैलो, एडेल
- बेस्ट रैप एल्बम : चांस द रैपर, कलरिंग बुक
- बेस्ट न्यू आर्टिस्ट : चांस द रैपर
- बेस्ट अर्बन कंटेम्पररी एल्बम : बेयोंसे, लेमोनेड
- बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस : मारेन मॉरिस, माय चर्च
- बेस्ट रॉक बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस : डेविड बोवी – ब्लैकस्टार
- बेस्ट रॉक सॉन्ग : ब्लैकस्टार –डेविड बोवी, सॉन्गराइटर (डेविड बोवी)
- बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम : डेविड बोवी – ब्लैकस्टार
- बेस्ट मेटल परफॉर्मेंस : मेगाडेथ– डिस्टोपिआ
- बेस्ट पॉप वोकल एल्बम : एडेल – 25
- बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस : एडेल – हैलो
- बेस्ट रैप परफॉर्मेंस : चांस द रैपर फीचरिंग लिल वेन और 2 चेंज (नो प्रॉब्लम)
- बेस्ट रैप/संग परफॉर्मेंस : ड्रेक – हॉटलाइन ब्लिंग
- पॉप डूओ/ग्रुप परफॉर्मेंस : स्ट्रेस्ड आउट – ट्वेन्टी वन पायलट्स
- बेस्ट कंट्रीएल्बम : स्टुगिल सिम्पसन – अ सेलर्स गाइडऑफ अर्थ
- बेस्ट कंट्री ड्यू/ग्रुप परफॉर्मेंस : पेंटाटोनिक्स फीचरिंग डॉली पर्टोन (जोलेन)
- बेस्ट कंट्रीसॉन्ग : लोरी मैककेन, सॉन्गराइटर (टिम मैकग्रॉ) – हम्बल एंड काइंड
- बेस्ट रॉक एल्बम : केज द एलिफेंट – टेल मी ए एम प्रिटी
- बेस्ट रैप सॉन्ग : ऑब्रे ग्राहम और पॉल जैफरीज, गीतकार (ड्रेक) – हॉटलाइन ब्लिंग
- बेस्ट आर एंड बी एल्बम : हैथअवे (लालाह हैथअवे लाइव)
- बेस्ट आर एंड बी सॉन्ग : हाड डेविड एंड म्यूज, सॉन्गराइटर्स (मैक्सवेल) – लेक बाए द ओशन
- बेस्ट आर एंड बी परफॉर्मेंस : सोलंग – क्रेन्स एन द स्काय
- बेस्ट ट्रेडिशन आर एंड बी परफॉर्मेंस : लालाह हैथवे– एंजल
- वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम : सिंग मी होम – यो – यो मा एंड ल सिल्क रोड़ आन्साम्बल
- फॉक एल्बम : सारा जारोस – अंदरकरंट
- बेस्ट अमेरिकन एल्बम : विलियम बेल – दिस इज वेयर आई लिव
- बेस्ट अमेरिकन रुट्स सॉन्ग : विन्स गिल, सॉन्गराइटर (द टाइम जम्पर्स) – किड सिस्टर
- बेस्ट अमेरिकन रुट्स परफॉर्मेंस : सारा जारोस – हाऊस ऑफ मर्सी
- रीजनल रुट्स म्यूजिक एल्बम : कलानी – ई वालेए
- बेस्ट ब्लूग्रास एल्बम : मार्क ओश्कॉनर विद ओश्कॉनर बैंड – कमिंग होम
- रेग एल्बम : जिग्गी मार्ले– जिग्गी मार्ले
- बेस्ट ट्रेडिशनल ब्लूज एल्बम : बॉबी रश – पॉर्क्यपाइन मीट
- बेस्ट कंटेम्पररी ब्लूज एल्बम : फैंटास्टिक नगरिटो – द लास्ट डेज ऑफ ओकलैंड
- कंटेम्पररी इन्स्ट्रूमेंटल एल्बम : सनकी पप्पी– कुलुचा वुलचा
- बेस्ट डांस रिकॉर्डिंग : द चौनस्मोकर्स डॉन्ट लेट मी डाऊन
- बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम : फ्लूम – स्किन
- बेस्ट न्यू ऐज एल्बम : व्हाइट सन – व्हाइट सन II
- बेस्ट इम्प्रोवाइज्ड जैज सोलो : जॉन स्कोफिल्ड, सोलोइस्ट – आई एम सो लोन्सम आई कुड क्राय
- बेस्ट जैज वोकल एल्बम : ग्रेगरी पोर्टर – टेक मी टू द ऐली
- जैज इंस्ट्रूमेंटल एल्बम : जॉन स्कोफिल्ड – कंट्री फॉर ऑल्ड मैन
- बेस्ट लार्ज जैज आन्साम्बल एल्बम : टेड नैश बिग बैंड – प्रेजिडेंशल सूट : एट वेरीऐशन ऑन फ्रीडम
- बेस्ट लैटिन जैज एल्बम : चूचो वाल्डेस – ट्रिब्यूट टू इराकेरे : लाइव इन मरसीसअ
- गॉस्पल परफॉर्मेंस/सॉन्ग : टमेला मनय किर्क फ्रैंकलिन, सॉन्गराइटर – गोड प्रोवाड
- गॉस्पल एल्बम : किर्क फ्रैंकलिन – लोसिंग माई रिलिजन
- कंटेम्पररी क्रिश्चन म्यूजिक एल्बम : हिलेरी स्कॉट और स्कॉट फैमिली – लव रिमैन्स
- बेस्ट रुट्स गॉस्पल एल्बम : जॉय रोरी– हिम

पुरी के अलावा, हॉलीवुड के कैरी फिशर, प्रिंस, जेने वाइल्डर, माइकल किमिनो, पैटी ड्यूक, गैरी मार्शल, एंटन येल्चिन, मैरी टैलर मूर, कर्टिस हैनसन और जॉन हर्ट को श्रद्धांजलि दी गई।

ऑस्कर अवॉर्ड में लोग जितना विनर्स को लेकर जानना चाहते थे, उससे कहीं ज्यादा नजरें सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस पर भी थीं। ऑस्कर के रेड कारपेट पर प्रियंका चोपड़ा जहां डिजाइनर राल्फ एंड रूसो के सिल्वर गाउन में नजर आईं, तो वहीं स्लमडॉग मिलियनेयर के एक्टर देव पटेल मां अनीता पटेल के साथ व्हाइट कोट और ब्लैक ट्राउजर में दिखे। उनके अलावा रुथ नेगा, सोफिया कार्सन, ताराजी पी हेनसन, जेसिका बील और जस्टिन टिम्बरलेक और एमा स्टोन जैसे स्टार्स भी नजर आए।

●●●